सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-29 अंक-5 7 से 21 मार्च, 2014 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य : 2 रुपये

विश्व सर्वहारा के महान नेता कार्ल मार्क्स की याद में

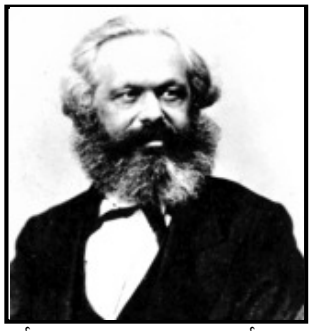

5 मई, 1818 - 14 मार्च, 1883

''बुर्जुआ समाज में पूंजी ही है स्वतंत्र और उसी की स्वतंत्रता है; जीवंत मनुष्यों की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, वे पराधीन हैं, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है।'' **– कार्ल मार्क्स**

विश्व सर्वहारा के महान नेता स्टालिन की याद में

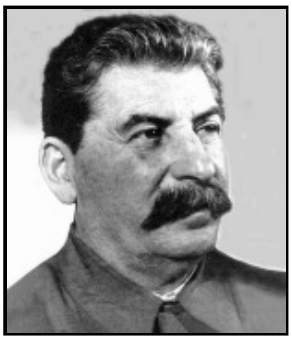

21 दिसम्बर, 1879 - 5 मार्च, 1953

''अतीत में, बुर्जुआ वर्ग ने खुद को केवल वचन में उदार होने दिया था, बुर्जुआ जनतांत्रिक स्वतंत्रता का चैम्पियन बना था और ऐसा करके लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल की थी। किन्तु अब असल में उसमें उदारता लेशमात्र भी नहीं बची है। तथाकथित ''व्यक्ति-स्वतंतंत्रता'' का बिन्दुमात्र भी अवशेष नहीं रहा है। व्यक्ति-स्वतंत्रता केवल उन्हीं को है जो पूँजी के मालिक हैं। बाकी सभी नागरिक हैं मानवदेही कच्चा माल; वे महज शोषण के लिए फिट माने जाते हैं। व्यक्ति और राष्ट्र के समानाधिकार आज बूटों के तले रौंदे जा रहे हैं। इनकी जगह मुठ्ठी भर चंद शोषकों के लिए हर तरह के अधिकारों ने ले ली हैं और शोषित बहुसंख्यकों को कोई अधिकार ही नहीं है। बुर्जुआ जनतंत्र और मुक्ति का झण्डा धूल में फेंका हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर बहुसंख्यक जनता को अपने साथ जुटाना चाहते हैं तो आप, कम्युनिस्ट और जनवादी पार्टियों के प्रतिनिधियों को यह झण्डा उठा कर चलना होगा। उसे उठाने वाला और कोई नहीं है।''

– स्टालिन (सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं पार्टी कांग्रेस में भाषण)

आगामी लोकसभा चुनाव 2014 के अवसर पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) केन्द्रीय कमेटी की जनता से अपील

एक बार फिर जनता लोकसभा चुनाव का सामना कर रही है। दो प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रीय बुर्जुआ पार्टियों–कांग्रेस और भाजपा के अलावा तमाम क्षेत्रीय बुर्जुआ पार्टियां और सोशल डेमोक्रेट, छद्म कम्युनिस्ट सीपीएम, सीपीआई सभी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही वे खुद को ''विकास'' की 'हिमायती' तथा 'भ्रष्टाचार' के खिलाफ लड़ने वाला 'योद्धा' बता रही हैं। हमेशा की तरह मीडिया उनके लम्बे-चौड़े दावे, वायदे और एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने को जोर-शोर से प्रचारित कर रहा है।

1952 के पहले आम चुनाव से ही जनता अनेक चुनावों तथा सरकारों के परिवर्तन की गवाह रही है। लेकिन इससे आम जनता के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? क्या हम लोगों की जीवन की दशा में तनिक भी सुधार देख पाते हैं? विभिन्न झंडों-बैनरों वाली ये पार्टियां जितने भी बड़े-बड़े दावे क्यों न करें, वास्तव में अकूत मुनाफा कमाने के जरिये कुछ एकाधिकारी पूंजीपतियों, कारपोरेट घरानों और बड़े व्यापारिक घरानों का ही विकास हुआ है। करोड़ों आम जनता की बर्बादी की कीमत पर इन्होंने अकूत मुनाफा कमाकर विशाल सम्पत्ति अर्जित की है। इसलिए यह अचरज की बात नहीं है कि लाखों लोग लगातार घोर गरीबी, भुखमरी और इलाज के अभाव में जी रहे हैं। 77 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनकी औकात रोजाना 20 रुपये खर्च करने की भी नहीं है। लाखों किसान-खेतिहर मजदूर रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं। लाखों लोग कर्ज के जाल में फंसकर आत्म हत्याएं कर रहे हैं। भिखमंगी, वेश्यावृत्ति, महिलाओं की तस्करी, महिलाओं तथा बच्चों की बिक्री तथा उनके खिलाफ अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर अरबपतियों की सूची में भारत का स्थान 5वां है, जहाँ 122 अरबपति हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े अरबपतियों की हालिया सूची में भारत के 5 अरबपति शामिल हैं। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे करीब-करीब तमाम बुर्जुआ पार्टियों के नेता-मंत्री अरबों रुपये की धन-दौलत के मालिक हैं। यहाँ तक कि भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक लोकसभा के 543 सदस्यों में से 321 अरबपति तथा 180 करोड़पति हैं, जो ज्यादातर कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय पार्टियों, यहाँ तक कि सीपीएम, सीपीआई के भी हैं। हाल में स्वीस बैंक अधिकारियों के खुलासे ने उजागर किया है कि भारतीय उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के व्यक्तिगत खातों में 72 लाख करोड़ रुपये की विशाल राशि जमा है। यह काला धन ही तो है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है।

केन्द्र और राज्य में सत्तासीन ये पार्टियाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, कारपोरेट घरानों और एकाधिकारी पूंजीपतियों के आदेश पर भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों को लागू करने में अपनी दक्षता और वफादारी को साबित करने के लिए एक दूसरे को पछाड़ने की गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा में लिप्त हैं। नतीजतन कल-कारखानों में लगातार श्रमशक्ति को घटाया जा रहा है, छंटनी-तालाबंदी हो रही है। पदों को समाप्त किया जा रहा है। स्थायी कामों के बदले ठेके पर काम हो रहे हैं। कार्य-काल में बढ़ोतरी हो रही है। काम का बोझ बढ़ रहा है। आउटसोर्सिंग हो रही है। वेतन और मजदूरी में कटौती हो रही है। एक तरफ राज्यों और केन्द्र की सरकारें मजदूरों के तमाम अधिकार छीन रही हैं, दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्रों को निजी मालिकों को सौंपा जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कारपोरेट घरानों को खदानों, खेती की जमीनों, नदियों के पानी और थोक व खुदरा व्यापार आदि पर भी नियंत्रण कायम करने की अनुमति दी जा रही है। टैक्स छूट, टैक्स माफी तथा बेल आउट के रूप में औद्योगिक घरानों को बड़ी मात्रा में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नतीजतन वित्तीय घाटा हो रहा है, जिसका सारा बोझ बढ़े हुए करों तथा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

यूक्रेन में गृहयुद्ध भड़काने की साम्राज्यवादी साजिश की आईएसीसी ने निन्दा की

इण्टरनेशनल एण्टी-इम्पीरियलिस्ट कॉ-ऑर्डिनेटिंग कमेटी (आईएसीसी) के महासचिव माणिक मुखर्जी ने यूक्रेन में साम्राज्यवादियों द्वारा भड़काए गए संघर्ष पर 23 फरवरी, 2014 को निम्नलिखित बयान जारी किया:

अमेरिका और यूरोपियन यूनियन (ईयू) द्वारा भड़काए गए गृहयुद्ध की कगार पर खड़ा है यूक्रेन। नाटो शक्तियाँ यूक्रेन को अपने दायरे में लाने के लिए कटिबद्ध थी और कुछ अरसा पहले ईयू ने थोड़ी सी कर्ज राशि की पेशकश यूक्रेन से की थी लेकिन इसके साथ शर्त जुड़ी थी कि ईयू पूँजी के प्रवेश के लिए यूक्रेनियन बाजार को खोलना होगा, मजदूरों पर मित्तव्ययता कदम थोपने होंगे और संघर्षों से अर्जित उनके हित लाभों में कटौती करनी होगी और यूक्रेन को नाटो मिलिट्री गठबंधन स्वीकारना होगा। यह वही नुस्खा था जिसने ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन में आर्थिक तबाही ला दी थी। राष्ट्रपति यांनुकोविच के नेतृत्वाधीन चुनी हुई यूक्रेन सरकार ने ईयू की पेशकश को खारिज कर दिया और पूँजीवादी रूस के साथ आर्थिक औद्योगिक सहयोग के करार पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी को लेकर मौजूदा संघर्ष की शुरूआत हुई। यूक्रेन पूँजीवादी रूस और पश्चिमी पूँजीपतियों के बीच प्रतियोतिगता का शिकार बन गया लेकिन लोगों के हितों की अनदेखी की गई। पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें (यूएसए और ईयू) यूक्रेन पर रूस के कब्जे को तोड़ने के लिए कटिबद्ध थे और उन्होंने कीव में यांनुकोविच-विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के लिए विरोधी ताकतों को भड़काया और मदद दी। हेलमेट और मास्क पहने घातक हथियारों से लैस सशस्त्र प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के साथ हिंसक संघर्ष में जुट गए। हिंसा में प्रदर्शनकारी और पुलिसमैन दोनों मरे थे और पश्चिम

(शेष पृष्ठ 7 पर)

लोकसभा चुनाव..

(पृष्ठ 1 का शेष)

जनकल्याणकारी योजनाओं में कटौती के रूप में आम आदमी पर लादा जा रहा है। लगातार महंगाई, टैक्स वृद्धि, मुद्रास्फीति, रुपये का अवमूल्यन जनता के जीवन को दयनीय बना रहा है। किसानों को विस्थाति कर सेज के लिए खेती की जमीनों को बलपूर्वक लिया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं–चक्रवात, बाढ़, सुखाड़ से हजारों लोगों का जीवन बर्बाद होता है, फसलों और सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा रोकथाम के न कोई कदम उठाये जाते हैं और न ही कोई समाधान निकाला जाता है। बीज, खाद, बिजली, कीटनाशकों के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जबकि किसानों को समर्थन मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। व्यापारियों, जमाखोरों और कालाबाजारियों को छूट है कि वे अपनी मर्जी से चीजों के दामों में हेराफेरी करें। केन्द्र व राज्य–दोनों सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती कर रही हैं तथा इन क्षेत्रों को औद्योगिक तथा व्यावसायिक घरानों को सौंप रही हैं ताकि वे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा– दोनों काफी महंगे हो गये हैं और आम लोगों की पहुँच से दूर चले गये हैं। पाठ्यक्रमों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और वैज्ञानिक समझ और नजरिया विकसित होने की बजाय तमाम मूल्यों और सामाजिक सरोकारों से रहित अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और फासीवादी संस्कृति पैदा हो। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के शिक्षा के दरवाजे बंद करने के मकसद से आम छात्रों के लिए स्कूलों में परीक्षा प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है, जबकि अमीरों के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में यह प्रथा बहाल है। सत्ताधारी वर्ग की विश्वस्त पार्टियां इसे ही 'विकास' और 'सुशासन' के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। सबसे प्रासंगिक सवाल है कि विकास किसके लिए हो रहा है?

पूर्ववर्ती अनुच्छेद आज की संकटग्रस्त और मरणासन्न पूँजीवादी व्यवस्था की असली तस्वीर पेश करते हैं। आज की पूँजीवादी व्यवस्था 18वीं-19वीं शताब्दी के पूँजीवादी राज्यों–जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए सामंती, तानाशाही और राजतंत्रात्मक शासन के खिलाफ क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी थी; धार्मिक कुसंस्कार के विपरीत धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद को सामने लाये थे; 'बराबरी', 'आजादी' और 'भाईचारे' के परचम को बुलन्द किया था और उस ऐतिहासिक स्थिति में जहाँ तक संभव था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संघर्ष किया था और इसे कायम किया था– से पूरी तरह से भिन्न है। आज का पूँजीवादी राज्य अपने प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवाद के मरणासन्न दौर में उस परचम को पैरों तले रौंद चुका है। आज यह पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी, दमनकारी और फासीवादी बन गया है और यह तमाम जन आंदोलनों, मजदूर वर्ग के संघर्षों और सभी जनवादी मूल्यों, नियमों व व्यवहारों को निर्ममता से दबा रहा है। मरणासन्न विश्व पूँजीवाद के अभिन्न अंग के तौर पर भारतीय पूँजीपति वर्ग 1947 में अपने सत्ता पर काबिज होने से लेकर अब तक उसी प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण करता आया है। आज कुछ मुट्टीभर लोगों के हाथों में एकाधिकारी पूँजी के केन्द्रीकरण, राज्य के हाथों में राजनीतिक सत्ता के केन्द्रीकरण तथा चिंतन के रेजिमेंटेशन की वजह से देश फासीवाद के खतरे का सामना कर रहा है। क्षेत्रीय पूँजी का प्राधान्य अभी तक भी हमारी अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो फासीवाद के पूर्ण रूपेण विकास में अवरोध का काम करती है। आज का बुर्जुआ वर्ग जनवादी नीतियों, मानवीय मूल्यों की तनिक भी परवाह नहीं करता है और न ही वह देश व इसकी जनता से कोई सरोकार रखता है। इसका एकमात्र सरोकार है कि चाहे कैसे भी हो निर्मम शोषण के जरिये अधिक से अधिक मुनाफा बटोरना। इसके लिए जनता और कुछ नहीं बल्कि शोषणमूलक मशीन का निवाला बनने वाला कच्चा माल है और पूरा देश लूटने के लिए विशाल बाजार के सिवा और कुछ नहीं है। यह पूरी तरह से अमानवीय, अनैतिक और भ्रष्ट हो गया है। इसलिए यह अप्रत्याशित नहीं है कि सत्ताधारी दलों मसलन कांग्रेस, भाजपा, क्षेत्रीय पार्टियों के नेता-मंत्री शासक पूँजीपति वर्ग की सेवा करते हुए भ्रष्ट, पाखंडी और जनविरोधी हो गये हैं। यहां तक कि सीपीआई (एम) के कुछ नेता भी भ्रष्ट आचरण के शिकार हैं। सत्ता में रहते हुए इन पार्टियों ने न सिर्फ जनविरोधी नीतियों को लागू किया, जन आन्दोलनों और वर्ग संघर्षों का सख्ती से दमन किया, बल्कि जनता की नैतिक रीढ़ को भी नष्ट करने का प्रयास किया है। वे भारतीय नवजागरण, आजादी आंदोलन और खासकर इसकी क्रांतिकारी धारा की गौरवशाली परम्परा को इतिहास से मिटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यह युवा पीढ़ी को नैतिक तौर पर बर्बाद करने तथा अमानवीय बनाने की बदनीयत से किया जा रहा है ताकि उनकी चिंतन क्षमता, विरोध की आवाज और संघर्ष का साहस खत्म हो जाये। प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में सेक्स, ब्लू फिल्मों, अश्लील साहित्यों, हिंसा, ड्रग, शराबखोरी तथा जुआखोरी आदि के प्रचार-प्रसार के जरिये छात्रों और नौजवानों को अनैतिक गतिविधियों की ओर धकेला जा रहा है। इसलिए यह अचरज की बात नहीं है कि आज भारत महिलाओं की तस्करी, अपहरण, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या में दुनिया में सबसे ऊपरी पायदान पर है। यहां तक कि कुछ महीने की बच्चियों तथा साठ साल से ऊपर की महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले जानवर नहीं हैं, बल्कि किसी भी मानवीय चेतना और मूल्यों से रहित मनुष्यों की नई प्रजाति हैं जो अध:पतित पूँजीवादी संस्कृति की उपज है। इस प्रकार पूँजीवाद जीवन को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक तौर से बर्बाद कर रहा है। यह सामाजिक और पारिवारिक जीवन की शांति को तबाह कर रहा है। पूँजीवाद सामाजिक प्रगति में मुख्य रुकावट के रूप में खड़ा है और इसकी जगह पर एक नयी व्यवस्था यानी समाजवादी व्यवस्था कायम करने की जरूरत है। यही मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉमरेड शिवदास घोष चिंतन की ऐतिहासिक सीख है।

चुनावों के जरिये मात्र सरकारें बदलती हैं, लेकिन शोषणमूलक पूँजीवादी समाज और इसकी दमनकारी स्टेट मशीनरी नहीं बदलती। चुनावों के जरिये सत्ताधारी बुर्जुआ वर्ग अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ अपने राजनैतिक मैनेजर को पुनर्स्थापित करता है या बदलता है, जनता को धोखा देता है और उसे क्रांति के रास्ते से भटकाता है। इसके अलावा, किसी भी हालत में यह जनता के सही जनादेश को प्रतिबिम्बित नहीं करता है बल्कि इसमें धनबल, बाहुबल, मीडिया बल के इस्तेमाल के जरिये पूँजीपति वर्ग का जनादेश ही प्रतिबिम्बित होता है।

कांग्रेस कई दशकों तक केन्द्र और राज्यों की सत्ता में रही है। भाजपा भी दो बार केन्द्र की सत्ता में रह चुकी है और अभी भी कई राज्यों में सत्ता में बनी हुई है। क्षेत्रीय पार्टियां मसलन एसपी, बीएसपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली दल, शिव सेना, एनसीपी, जदयू, बीजेडी, टीडीपी, एजीपी, सीपीएम, टीएमसी इत्यादि सभी पार्टियाँ विभिन्न राज्यों में सत्ता में रह चुकी हैं या अब भी सत्ता में बनी हुई हैं। इनके नामों और झंडों में फर्क के सिवाय दरअसल इनकी नीतियों या इनके शासन करने के ढंग में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस अपने को 'सेकुलर पार्टी' होने का दावा करती है और सीपीएम, सीपीआई जैसी तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टियों ने हमेशा ही उसकी इस छवि को तैयार करने में मदद दी है। हालांकि उन्होंने जिस पर अमल किया, वह धर्मनिरपेक्षता नहीं, बल्कि तमाम धर्मों को समान प्रोत्साहन या सर्व धर्म समभाव है। लेकिन ऐतिहासिक और वैचारिक तौर पर सही धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य और शिक्षा सहित उसकी तमाम संस्थाएं धार्मिक प्रभाव से अलग-थलग होंगी और इसके मामलों का संचालन धर्मनिरपेक्ष जनवादी सिद्धातों के आधार पर होगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को हर व्यक्ति का अपना निजी मामला मानता है। न तो वह किसी के धार्मिक मामलों में प्रोत्साहन देता है और न ही उसमें हस्तक्षेप करता है। वह धर्म में विश्वास रखने वाले और धर्म में विश्वास न रखने वाले दोनों को बराबर मानता है। तमाम धर्मों को समान प्रोत्साहन देने के नाम पर कांग्रेस नेतृत्व ने आजादी आंदोलन के दौरान वस्तुत: ऊंची जाति के हिन्दुओं की राजनीति की, जिसने मुसलमानों, तथाकथित 'नीची जाति' के हिन्दुओं को आजादी आंदोलन से विमुख कर दिया, जनता में फूट पैदा हुई और इस प्रकार देश को बांटने के लिए अंग्रेजों को मौका मिल गया। वोट बैंक तैयार करने तथा मेहनतकश अवाम को बांटने के एकमात्र इरादे से कांग्रेस ने 1984 के सिख-विरोधी दंगे सहित अनेक दंगे भड़काये। अपने को 'हिन्दुत्व' का चैम्पियन होने का गर्व के साथ दावा करने वाली भाजपा ने आडवाणी की रथ यात्रा के जरिये मुस्लिम विरोधी उन्माद फैलाया, बाबरी मस्जिद को ढाहा और गोधरा ट्रेन दुर्घटना के बाद 2500 से ज्यादा मुसलमानों का नरसंहार करवाया। आश्चर्य होता है कि क्या ये कट्टरपंथी उन्मादी चैतन्य, रामकृष्ण और विवेकानंद से भी बड़े हिन्दू हैं और क्या वे सचमुच हिन्दू कहलाने के काबिल हैं? ऐसा इसलिए कि हिन्दुत्व के इन महान प्रचारकों ने बाबरी मस्जिद को ढाहने और उसकी जगह पर राम मंदिर बनाने की बात सपने में भी नहीं सोची होगी। वरन् इन सभी ने अपने पूरे जीवन में विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच सौहार्द का ही उपदेश दिया। गोधरा की घटना के बाद नरसंहार के रचियता श्री नरेन्द्र मोदी, जिनके हाथ सैकड़ों निर्दोष मुसलमान स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के खून से रंगे हुए हैं, जिन्हें भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने राज धर्म को नहीं निभाने पर सख्ती से डांट पिलायी थी, उसी को भाजपा द्वारा भारत के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर सामने लाया जा रहा है। केन्द्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कुशासन के खिलाफ जनता में पैदा हुए असंतोष और नफरत का फायदा उठाकर भाजपा साम्प्रदायिक आधार पर जनता का ध्रुवीकरण कर हिन्दू वोट बैंक निर्माण करने के उद्देश्य से इस घोर हिन्दू साम्प्रदायिक नेता को सामने ला रही है। सैकड़ों गरीब किसानों को उनकी जमीन से जबरन बेदखल कर खेती की जमीन का एक बड़ा भाग विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए कारपोरेट घरानों को देकर और उनको सस्ती दर पर बिजली-पानी देने, सब्सिडी बढ़ाने का आश्वासन देकर और अंतत: मजदूर वर्ग की ओर से कोई अशांति न होने देने का आश्वासन देकर कारपोरेट घरानों का विश्वास जीत लेने पर ताकतवर औद्योगिक घराने अब मिस्टर मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजैक्ट करने के लिए करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं।

अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ, जिन्हें सीपीएम, सीपीआई 'धर्मनिरपेक्ष मित्र' मानती हैं, खुलेआम जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, संकीर्णतावाद की राजनीति करती हैं और 'वोट बैंक' तैयार करने के लिए क्षेत्रीय, नस्लीय व भाषाई भावना फैलाती हैं। अविभाजित सीपीआई और बाद में विभाजित होकर बनी सीपीएम, सीपीआई व सीपीआई (एमएल) के अन्य कई गुट कभी सही मार्क्सवादी पार्टी नहीं थे। अपने सुधारवादी नजरिये के साथ सीपीआई, सीपीआई (एम) ने साठ के दशक के मध्य तक जरूर कुछ जन आंदोलन संगठित किये थे। लेकिन सत्ता का स्वाद चखने के बाद से लम्बे समय तक अब वे संसदीय राजनीति और सुविधाओं के प्रति इतना आसक्त हो गये हैं कि उन्होंने ऐसे हालात में भी जब शोषित-पीड़ित जनता का विशाल तबका आंदोलन के लिए बेचैन है, संघर्ष के मैदान को त्याग दिया है। संसद और विधानसभाओं में कुछ सवालों को उठाना और कुछ बयान जारी करने तक ही आज उनकी सारी गतिविधि सिमटकर रह गयी है। सिर्फ यही नहीं, जब वे पश्चिम बंगाल तथा केरल में सरकारी सत्ता में थे, तो उन्होंने एकाधिकारी पूँजीपति घरानों, बड़े व्यवसायियों तथा विदेशी साम्राज्यवादियों के हित में निर्ममता के साथ मजदूर-किसानों के आंदोलन तथा जनवादी आंदोलनों को दबाने और खत्म करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। उन्होंने कई बार खुले आम या गुप-चुप तरीके से कांग्रेस से गठजोड़ किया। यहाँ तक कि सीपीआई (एम) ने जनता को गुमराह करने के लिए इस या उस बहाने कभी-कभी भाजपा के साथ गठजोड़ किया ताकि सत्ता के गलियारे तक पहुंचा जा सके। वर्तमान में इनकी एकमात्र कोशिश कुछ चुनावी फायदों के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट करना तथा कांग्रेस को वर्तमान संकट से उबारना है। बेशक ये दोनों तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टियां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर करीब-करीब ब्रिटिश लेबर पार्टी की तरह पूरी तरह से संविधानवादी संसदीय पार्टी बन गयी हैं। नतीजतन जनवादी जन आंदोलन के क्षेत्र में एक शून्यता पैदा हो गयी है। आंदोलन की ताकतवर जनवादी शक्तियों को न पाकर जनवाद पसंद बुद्धिजीवियों

(शेष पृष्ठ 7 पर)

संसदीय चुनाव में क्रान्तिकारी क्यों और किस दृष्टिकोण से भाग लें – शिवदास घोष

जब तक क्रान्ति नहीं हो जाती, तब तक जनता चुनाव चाहे या न चाहे, पसंद करे या न करे, अच्छा लगे या बुरा लगे, जनता को इनमें खींच लिया जाता है और जनता इसमें आ भी जाती है। क्रान्ति का मतलब है जब जनता ने समझ लिया हो कि चुनाव की जरूरत नहीं रही, जब सब इस चेतना के आधार पर संगठित हो गए हों और संगठित रूप से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हों, नकारात्मक बहिष्कार नहीं, बल्कि सकारात्मक रूप से कर रहे हों, वे जनउभार, जन अभ्युत्थान करने के मुकाम पर पहुँच गए हों, जब जनता कहती हो, ''नहीं, अब चुनाव नहीं, सत्ता दखल करो'' केवल मात्र तभी चुनाव में भाग लेना अकार्यकारी और गैर जरूरी हो जाता है, वरना चुनाव में जनता बार-बार फंस जाती है और जनता के साथ रहने की खातिर क्रान्तिकारी हो या गैर क्रान्तिकारी – सभी को चुनाव में जाना पड़ता है। सही मायने में क्रान्तिकारियों को भी इसमें जाना पड़ता है। सिर्फ इस तरह के संकीर्ण स्वर्यसिद्धवाद पर अमल करते हैं, जो क्रान्तिकारी राजनीति नहीं करते हैं, केवल वे ही इससे कन्नी काटना और इससे बाहर रहना चाहते हैं, वरना बाकी सभी को चुनाव में जाना पड़ता है। तब चुनाव में जो भाग लेंगे उन सभी का दृष्टिकोण क्या एक होगा? ऊपर से देखने में चुनाव तो सभी लड़ते हैं, मैं लड़ता हूँ, हम क्रान्तिकारी मार्क्सवादी-लेनिनवादी भी चुनाव लड़ते हैं, सोशल डेमोक्रेट भी चुनाव लड़ते हैं, असली ताकतें भी चुनाव लड़ती हैं और नकली तत्व भी चुनाव लड़ते है, बुर्जुआ पार्टियाँ भी चुनाव लड़ती हैं और छद्म समाजवादी भी चुनाव लड़ते हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि ये सब एक ही हैं। वे सभी कहेंगे मै सही हूँ, विरोधी पार्टियाँ गलत हैं। तब तो विरोधी पार्टियों को हराने के लिए कोई भी हथकण्डा या कदम जायज है, क्योंकि मैं सही हूँ– इस तरह की दलील अगर आप देते रहें, तो बुर्जआ वर्ग और आप में कोई वर्गगत फर्क नहीं रह जाता है। दृष्टिकोण का भी फर्क नहीं रहता है। दरअसल, गहन विचार-विश्लेषण से यह बात गलत साबित हो जाती है।

गौरतलब है कि बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग, इन दोनों की ही लड़ाई के कला-कौशल, कायदे, संगठन के सिद्धांत, चुनाव संबंधी दृष्टिकोण, जीत के कला-कौशल व हार के प्रति रवैये का निर्धारण भी देश के वास्तविक क्रान्तिकारी आन्दोलन के स्तर और जनचेतना के मान के आधार पर ही होता है। बुर्जुआ पार्टियों का मूल उद्देश्य है चुनावों में येन-केन-प्रकारेण ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटें हथियाना और ऐसा करके सत्तासीन होना। सत्तासीन होकर वे इस मौजूदा व्यवस्था को ही बरकरार रखने के लिए कुछ सुधार-संशोधन करती हैं, कुछ झूठे नारे देती हैं। जिस तरह की बात बोलने से मैं जनता में प्रगतिशील लगूँ, कुछ दिन जनता को गुमराह कर सकूँ, बेवकूफ बना सकूँ और इस व्यवस्था को दीर्घस्थाई बना सकूँ–यही है उनका उद्देश्य। तब उनका मूल लक्ष्य है चुनाव में जैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा सीट दखल करना। इसके अलावा राजनैतिक कार्यक्रम, फौरी काम का एजेण्डा भी वे पेश करते हैं। ये कार्यक्रम और नारे उनके चाहे जो भी हों, उनका एकमात्र उद्देश्य है 'ग्रेब मेक्सिमम सीट्स'। (ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाना)

इसके उलट, क्रान्तिकारी उद्देश्यमुखिता के लक्ष्य से सर्वहारा वर्ग की पार्टी लोगों के साथ रहने की जरूरत से मजबूर होकर चुनावों में भाग लेती है, तब वह जनता की क्रान्तिकारी राजनैतिक लाइन के आधार पर चुनाव में जाती है। सीटें जीतने की भी वह भरसक कोशिश करती है। लेकिन उसके उद्देश्य का केन्द्र बिन्दु येन-केन-प्रकारेण ज्यादा से ज्यादा सीटें दखल करना कभी नहीं होता। क्रान्तिकारी पार्टी का मेन फोकल प्वाइण्ट जनता की क्रान्तिकारी लाइन के आधार पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है इसके बारे में लोगों को शिक्षित करना होता है और ऐसा करते हुए अगर हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें तो सब से बेहतर है, अगर नहीं हासिल कर पाते हैं, एक सीट भी नहीं हासिल हो, तो न हो। अगर दस को बचा पाते हैं तो दस की रक्षा करेंगे लेकिन उसका सेण्ट्रल फोकल प्वाइण्ट कभी भी येन-केन-प्रकारेण कुछ सीटें हथियाना कभी नहीं हो सकता।

व्हाट इज दैट मेन लाइन एण्ड मास स्टाइल ऑफ एक्टिविटी? जनता के उस क्रान्तिकारी राजनैतिक संघर्ष का तरीका क्या होगा जिसे चुनाव में जनसाधारण के पास मैं ले जाऊँगा? जनता के बीच मैं यह पैगाम लेकर जाऊँगा कि आप जब चुनाव में भाग ले ही रहे हो तो जनहित को ध्यान में रखते हुए क्रान्तिकारी राजनीतिक लाइन के आधार पर चुनाव में भाग लें। ऐसा करते हुए आप अपना गढ़ खुद संभालें। जितनी भी सीटें पा सको, ज्यादा से ज्यादा पाओ, यहाँ तक कि अगर सारी सीटों पर जीत सकते हो तो जीतो लेकिन जीतो केवल मात्र इसी क्रान्तिकारी राजनीतिक लाइन के आधार पर, इसमें गोलमाल मत कर देना। लेकिन इसकी बजाय अगर आप यह हौआ खड़ा करके कि 'दुश्मन को हराने के लिए जो भी जरूरी हो वह करना पड़ेगा' आप दुश्मन का मुकाबला करने के नाम पर और क्रान्तिकारी का चोगा पहन कर ऐसा करते हो, तब आप भी असल में वही हथकण्डा, वही कायदा और वही रण-कौशल अपना रहे हो जो हथकण्डा, कायदा और रण-कौशल अपना कर बुर्जुआ वर्ग चुनाव लड़ता है। निश्चित ही आप क्रान्ति के नाम पर यह सब करोगे। इससे क्या कोई क्रान्तिकारी बन सकता है? इससे क्या क्रान्ति का काम आगे बढ़ता है? नहीं, इस तरह से न तो कोई क्रान्तिकारी बनता है और न ही इससे क्रान्ति का काम आगे बढ़ता है। इससे जैसा हम कहते हैं कि चुनाव के जरिए बुर्जुआ संसदीय राजनीति का पर्दाफाश करेंगे क्या वह होता है? यह बात मुँह से कहना और करना क्या एक ही चीज होती है? कोई पार्टी सिर्फ बातें बनाती है और कोई पार्टी जो कहती है वह वास्तव में करती भी है। इसलिए कौन केवल बातें बनाती हैं और असल में कौन है जो कहती है उसके अनुसार काम करती है, इस करनी और कथनी में फर्क करने की राजनैतिक शिक्षा से लोगों को शिक्षित करना ही असल काम है।

.....

राजसत्ता की मशीनरी कहने से आप क्या समझते हैं? याद रखें राजसत्ता और सरकार एक चीज नहीं होती है। एक गोलमाल यहाँ हमेशा किया जाता रहा है। यह समझाया जाता है कि मानो सरकार ही सब कुछ है। मानो सरकार पर कब्जा कर लेने से ही राजसत्ता को जिस तरह मर्जी हो चलाया जा सकता है। यह कहा जाता है कि सत्यानाश की सारी जड़ सरकार में बैठे ये सब बुरे लोग हैं। उन्हें हटा कर अगर हमारे जैसे अच्छे लोग सरकार में जा सकें तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्रान्ति-व्रान्ति का हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस धारणा में न तो मार्क्सवाद-लेनिनवाद है और न ही राजसत्ता विज्ञान के बारे में सही धारणा है। इसमें निहित है राजसत्ता विज्ञान के बारे में घोर अज्ञानता, अथवा मनमाने ढंग से राजसत्ता के सवाल को, उसे उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी तैयारी को गौण करके देखना और लोगों को वोट की राजनीति में फंसाए रखना। आपको याद रखना चाहिए कि राजसत्ता के सवाल के बिना किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन के सवाल को सोचा भी नहीं जा सकता।

.....

संसदीय चुनावों के जरिए सरकार बदलने के बारे में यहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है। जब लोग एक सरकार विशेष से असंतुष्ट और विक्षुब्ध हो जाते हैं, तो चुनावों के जरिए एक अन्य सरकार आ जाती है। आम लोग कुछ व्यक्तियों को बेईमान मानते हैं; वे सोचते हैं कि सरकार उनका कल्याण करेगी बशर्ते कि बेईमान लोगों को हटाकर उनकी जगह ईमानदार लोगों को सरकार में सत्तासीन कर दिया जाये। ऐसा करने से ही उनका मंगल होगा। बुर्जुआ संसदीय राजनीतिज्ञ जिस किसी 'उसूल' या 'विचारधारा' की आड़ में लोगों को गुमराह करने और मूर्ख बनाने की बदनीयत से इस किस्म के प्रचार का सहारा लेते हैं। इसी वजह से मैं मजदूर-किसानों और आम लोगों को इस किस्म के झांसे के बहकावे में न आने का आग्रह करता हूँ। क्योंकि सिर्फ सरकार बदलने से ही आम लोगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है। संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत चाहे जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार दे दिये जाये, कायदे-कानून बना दिए जाएं और लोगों को राहत देने की चाहे जितनी भी योजनाएं ले ली जाएं, इनके द्वारा लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। बल्कि इनके द्वारा लोगों की हालत दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती जाएगी।

राज्य-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के बगैर ही किसी सरकार को बदल देने से क्या होता है? अगर ईमानदार व्यक्ति सरकार में सत्तासीन हो भी जाते हैं तो उससे तो और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है क्योंकि आम लोग उन पर विश्वास करते हैं। ईमानदार होने के बावजूद अगर वे गुमराह हों और क्रान्ति के रास्ते पर कदम न बढ़ा सकें तो उन्हें कार्यत: पूँजीवादी व्यवस्था ही सुधारनी तथा और भी ज्यादा मजबूत बनानी पड़ती है; जबकि उनके प्रति लोगों के विश्वास के फलस्वरूप कम से कम कुछ समय के लिए ही सही, जनता का विक्षोभ व असंतोष ठण्डा पड़ जाता है। इसलिए इन सब तथाकथित ईमानदार प्रशासकों के शासनकाल में सिर्फ बुर्जुआ शासन को, पूँजीवादी शासन को और ज्यादा सुदृढ़ करने और इसकी मजबूत नींव तैयार करने का ही अवसर प्राप्त होता है। जवाहरलाल के नेतृत्व में भी भारतीय पूँजीवाद की जड़ें इसलिए और भी ज्यादा गहरी व मजबूत हुई हैं और वह सुदृढ़ हुआ है। इसलिए लेनिन ने कहा था कि एक ईमानदार और बेईमान धर्मप्रचारक यानी पादरी में से बेईमान पादरी एक मायने में अच्छा होता है, इस अर्थ में नहीं कि वह अपनी बेईमानी की वजह से अच्छा होता है बल्कि वह इसलिए अच्छा होता है कि लोग उसे आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर एक ईमानदार जबकि भ्रमित धर्मप्रचारक यानी पादरी लोगों में यह प्रचार करना जारी रखे कि वे दुखी एवं मुसीबत के मारे इसलिए हैं कि उनकी नियति, तकदीर या किस्मत ही ऐसी है, ऐसा करते हुए लोगों को क्रान्ति से दूर रखने का उसका कृत्य लोगों को ज्यादा हानि पहुँचाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग उस पर विश्वास करते हैं और वह हर तरह के शोषण के खिलाफ संघर्ष से, जिस संघर्ष में उनकी मुक्ति निहित है, उससे कन्नी काटने और दूर रहने की जनता को शिक्षा देता रहता है।

नोट : ये उद्धरण इन किताबों से लिये गये हैं :

'ऑन प्रीजर्विंग यूनिटी एण्ड एस्टेबलिसिंग रेवोलूशनरी लीडरशिप इन वर्कर्स मूवमेंट'

15 अगस्त की आजादी और जनमुक्ति की समस्या

'निर्वाचनसर्वस्व राजनीति नय, विप्लवी आन्दोलनई मुक्तिर पथ'

देश भर में मनाया गया शहीद चंद्रशेखर आजाद का 83वां शहादत दिवस

दिल्ली

शालीमार बाग: 26 फरवरी को शहीद चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस एआईडीवाईओ तथा एआईएमएसएस की स्थानीय कमेटी ने मनाया। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संगठन की सचिव प्रकाश देवी के अलावा सुमन, मीना, शशि वधवा तथा दीपक ने सम्बोधित किया। सभा का संचालन एआईएमएसएस की स्थानीय अध्यक्ष नीतु खन्ना ने किया। **मुकुंदपुर:** 27 फरवरी को एआईडीवाईओ की मुकुंदपुर की यूनिट की ओर से शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन लोकल इंचार्ज कॉ. रामबदन ने अपना वक्तव्य रखते हुए किया। **बुराड़ी:** 27 फरवरी को एआईडीवाईओ की बुराड़ी यूनिट की ओर से शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन लोकल इंचार्ज कॉ. एम. सिंह ने अपना वक्तव्य रखते हुए किया। **कोटला:** 1 मार्च को एआईडीवाईओ की कोटला यूनिट की ओर से शहीद चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन लोकल इंचार्ज कॉ. नवीन ने किया तथा मीटिंग को संगठन के राज्य कार्यालय सचिव कॉ. प्रभाष ने सम्बोधित किया। **प्रतापबाग:** 1 मार्च को एआईडीवाईओ, एआईडीएसओ तथा एआईएमएसएस की ओर से शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर हुई मीटिंग को एआईडीवाईओ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य कॉ. अमरजीत ने मुख्य वक्ता के तौर पर सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन एआईडीएसओ की ओर से कॉ. मौसम रानी ने किया। सभा में एआईएमएसएस की ओर से कॉ. आशा भी मौजूद थी। **जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज :** 25 फरवरी, दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के बॉस्केटबॉल कोर्ट में शहीद चन्द्रशेखर आजाद का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शहीद चन्द्रशेखर आजाद से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख किया। उपस्थित छात्र-छात्राओं को कॉलेज की राजनैतिक विज्ञान की अध्यापिका श्वेता शर्मा ने वर्तमान काल में शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए छात्र-शिक्षा समस्याओं के खिलाफ आन्दोलन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि शोषणहीन समाज बनाने के शहीदों के अधूरे सपने को साकार करने का यही एकमात्र रास्ता है। सभा को ऑल इण्डिया डीएसओ के दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य कॉ. मो. आसिफ ने सम्बोधित किया। सभा का संचालन कॉलेज के तृतीय वर्ष के छात्र कॉ. श्रीराम ने किया।

उपरोक्त सभी जगह कार्यक्रम की शुरूआत शहीद चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई।

झारखण्ड

आदित्यपुर : सरायकेला-खरसवां जिला के आदित्यपुर स्थित कलूपटोंगा बस्ती में ऑल इण्डिया डीएसओ जिला कमेटी के तत्वावधान में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद का शहादत दिवस पूर्ण मान-मर्यादा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में ऑल इण्डिया डीएसओ राज्य कमेटी उपाध्यक्ष कॉमरेड विष्णुदेव गिरी, जिला सचिव कॉमरेड अन्नत कुमार महतो व विशाल वर्मा ने शहीद चन्द्रशेखर आजाद के जीवन-संघर्ष और चरित्र से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को उपस्थित छात्र-छात्राओं के समक्ष रखा। सभा का संचालन कॉमरेड दीपक कुमार ने किया और धन्यवाद कॉमरेड राजू कुमार ने किया।

पंजाब

बुढ़लाढ़ा : 27 फरवरी 2014 को आजादी आन्दोलन के शहीद चन्द्रशेखर आजाद के शहादत दिवस के अवसर पर शिक्षा के व्यापारीकरण, निजीकरण, फीस वृद्धि, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता व शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन (ए.आई.डी.एस.ओ.) व ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (ए.आई.डी.वाई.ओ.) के संयुक्त तत्वावधान में एक विरोध मार्च निकाला गया। जुलूस बुढ़लाढ़ा बस स्टैण्ड से शुरू होकर एस.डी.एम. ऑफिस पहुँचा जहां एक सभा की गई।

सभा को एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के पंजाब इकाई के सचिव कॉमरेड अमीन्दर पाल सिंह व ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉमरेड भास्करानन्द ने संबोधित किया। सभा का संचालन ए.आई.डी.एस.ओ. के बुढ़लाढ़ा इकाई के सचिव कॉमरेड संदीप सिंह ने किया।

वक्ताओं ने कहा कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक केन्द्र व राज्य सरकारें एक के बाद एक शिक्षा-विरोधी नीतियां लागू करती जा रही हैं। 8वीं कक्षा तक पास-फेल सिस्टम समाप्त कर छात्रों में पढ़ाई के प्रति गम्भीरता को खत्म किया जा रहा है। नशाखोरी को छात्रों-नौजवानों के अन्दर काफी बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे उनकी नैतिकता में भी भयंकर गिरावट हो रही है। वक्ताओं ने उपस्थित छात्र-नौजवानों से शिक्षा, संस्कृति और जनजीवन पर हो रहे तमाम हमलों के खिलाफ एकजुट होकर जुझारू आंदोलन खड़ा करने की अपील की।

सभा के अन्त में कॉमरेड संदीप सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने एस.डी.एम. को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमण्डल में परमिन्दर सिंह, हरविन्दर सिंह, सुखवीर और जसवीर शामिल थे।

हरियाणा

रोहतक : 27 फरवरी को छात्र संगठन ऑल इण्डिया डीएसओ और युवा संगठन ऑल इण्डिया डीवाईओ ने सरकारी नौकरियों में भर्तियों में धांधली, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, दाखिलों में सीमित सीटों, स्कूलों में बेरोकटोक पास प्रणाली, छात्राओं पर बढ़ते हमलों, अश्लीलता व नशाखोरी को बढ़ावा और खेलों में पैसे के बोलबाले का कड़ा विरोध किया।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर विभिन्न जिलों से आये छात्र-नौजवान पहले छोटूराम पार्क में इकट्ठे हुए जहां ऑल इण्डिया डीएसओ और युवा संगठन ऑल इण्डिया डीवाईओ के नेताओं ने उन्हें सम्बोधित किया। इसके बाद लघु सचिवालय तक

बुढ़लाढ़ा में विरोध मार्च निकालते हुए छात्र

प्रभावशाली विरोध प्रदर्शन करके उपायुक्त रोहतक को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देकर सरकार की शिक्षा-विरोधी व रोजगार-विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग की।

छात्र-नौजवानों ने स्कूलों समेत सरकारी विभागों में खाली पड़े हजारों पदों को हुड्डा सरकार द्वारा जानबूझ कर न भरे जाने और 9-10 साल तक झांसे देते रहने पर गहरा आक्रोश जताया। भाई-भतीजावाद, रिश्वतखोरी व राजनैतिक भेदभाव की कड़ी निन्दा की। धांधली से हुई एचसीएस भर्ती की उच्च न्यायालय के जज से जांच कराने की मांग की। सरकार खुद प्राइवेट कम्पनी की तरह ठेका प्रथा व गेस्ट प्रणाली लागू कर शोषण कर रही है। नये रोजगारों के अवसर सृजन करने की बजाय खेती योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर नाजायज अधिग्रहण कर परम्परागत रोजगारों को उजाड़ने का भी छात्र-नौजवानों ने कड़ा विरोध किया।

छात्र नेताओं ने पहली से आठवीं तक बेरोकटोक पास करने की सरकारी नीति को जनसाधारण परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की एक गहरी साजिश बताया। शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण को बढ़ावा देकर फीस वृद्धि और समेस्टर व ग्रेडिंग प्रणाली से शिक्षा को चौपट किया जा रहा है। सीमित संख्या में दाखिलों से छात्र मारे-मारे फिरते हैं। प्रवेश परीक्षा, पात्रता परीक्षा, इंटरव्यू, काउन्सलिंग आदि शिक्षा व भर्ती में रुकावट डालने के अलावा घोर भ्रष्टाचार व अनियमिताओं का जरिया बना हुआ है-इनमें योग्यता को ठुकराया जा रहा है।

युवा नेताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अश्लीलता, नशाखोरी, ड्रग्स, हिंसा, स्कूलों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देकर लोगों में, खासकर छात्र-नौजवानों में यौन विकृति, नशे की लत, कामुकता, बेमतलब हिंसा की प्रवृत्ति को पनपा रही है। इस तरह उन्हें अपराध की दुनिया में धकेला जा रहा है। छात्र-नौजवानों को इन्सानी गुणों व सामाजिक सरोकारों से वंचित कर देने की साजिश चल रही है। हर सरकार छात्र-युवा शक्ति को पंगू बना रही है ताकि उनका पूंजीपतिपरस्त व भ्रष्ट शासन निर्बाध रूप से जारी रहे। उन्होंने इसे नाकाम करने

(शेष पृष्ठ 6 पर)

रोहतक में विरोध प्रदर्शन करते छात्र-नौजवान

आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा यूपी विधान सभा का घेराव

लखनऊ (उ.प्र.) : 20 फरवरी को आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिक वेलफेयर एसोसिएशन जो एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध है के आह्वान पर प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी महिला कर्मियों ने लखनऊ में ऐतिहासिक विधान सभा मार्च तथा पांच घण्टे विधान सभा का घेराव किया। उ.प्र. में हमारी एसोसिएशन के प्रयास से दो अन्य आंगनबाड़ी संघों तथा मुख्य सेविकाओं व बाल विकास परियोजना अधिकारियों के संघों ने प्रथम बार इस संयुक्त कार्यक्रम को सफल बनाया। जिन लोगों ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखा, उनके मुँह से यही निकला कि महिला कामगारों का इतना बड़ा प्रदर्शन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा।

पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार एसोसिएशन के बैनर तले सुसज्जित जुलूस प्रात: 11 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन से गगन भेदी नारे लगाते हुए प्रारम्भ हुआ। उसी समय महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ तथा अन्य संघों का जुलूस बाल विकास एवं परियोजना निदेशालय इन्दिरा भवन से विधान सभा के लिए प्रारम्भ हुआ। ठीक 12 बजे दोनों जुलूस जब विधान सभा पर पहुँच कर सभा में बदल गए तब नजारा देखने लायक था। विधान सभा सत्र स्थगित हो गया तथा मंत्री विधायक पिछले दरवाजों से निकल गए। चार घण्टे तक सड़क जाम कर सभा चलती रही।

वक्ताओं ने कहा कि उ.प्र. सरकार जनहित की बेहद महत्वपूर्ण आईसीडीएस योजना का निजीकरण कर रही है तथा इसकी पके पकाए गर्म खाने की योजना जबरन एनजीओ को दी जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में सरकार पिछले 12 वर्ष से कोई वृद्धि नहीं कर रही जबकि महंगाई दिन रात बढ़ रही है तथा काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। उनका न तो कोई प्रोमोशन किया जा रहा है न ही सेवानिवृति पर कोई लाभ दिया जा रहा है। जुलूस व सभा का नेतृत्व एसोसिएशन की प्रदेश महासचिव शशिबाला, मिथलेश चौधरी, सोमवती शर्मा आदि ने किया। सभा को आंगनबाड़ी एम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इण्डिया (एईएफआई) की राष्ट्रीय अध्यक्षा कमलेश चहल, एआईयूटीयूसी के उ.प्र. राज्य कार्यालय सचिव कॉ. बालेन्द्र कटियार ने भी सम्बोधित किया।

उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

दिल्ली : 19 फरवरी को युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को ए.आई.डी.वाई.ओ., दिल्ली के एक प्रतिनिधिमण्डल ने ज्ञापन सौंपा। इसमें राज्य सचिव प्रकाश देवी के नेतृत्व में संगठन के अध्यक्ष राकेश कुमार के अलावा प्रभाष, रामबदन, अमरजीत, अतुल, एम.सिंह, संगीता, नवीन आदि शामिल रहे। उपरोक्त मांगों को लेकर दिल्लीभर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। ज्ञापन में भर्तियों पर लगा प्रतिबंध हटाने और रिक्त पड़े सभी पदों को शीघ्र भरने, ठेके पर नियुक्त कर्मचारियों को स्थाई करने व ठेकेदारी प्रथा को बंद करने, सभी को रोजगार देने तब तक जीने योग्य पर्याप्त बेरोजगारी भत्ता देने, 'रोजगार नीति बनाने' तथा रोजगार के लिए आवेदन शुल्क न लेने, शराब बिक्री पर अंकुश लगाने, अश्लील सिनेमा, गीत, विज्ञापनों आदि पर रोक लगाने और महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाने, दिल्ली की जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नए अस्पताल खोलने तथा साफ व गुणवत्तापूर्ण पानी देने की मांग की गई।

मदर ग्रुप व आंगनबाड़ी कर्मियों ने निकाला जुलूस

भिवानी (हरियाणा) : 28 फरवरी को ऑल इण्डिया यूटीयूसी से सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन हरियाणा और मदर ग्रुप महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने आंगनबाड़ी के बच्चों एवं अन्य लाभार्थियों के लिए पोषाहार बनाने में आने वाली समस्याओं व सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने आदि मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। इससे पूर्व वे नेहरू पार्क में एकत्रित हुई और हांसी गेट होते हुए प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय में पहुँची। प्रदर्शनकारियों को मदर ग्रुप यूनियन नेत्री मिसरो और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की महासचिव पुष्पा दलाल ने सम्बोधित किया।

अतिक्रमण के नाम पर एचईसी प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा लगातार उजाड़ने की कोशिश के खिलाफ जारी है बस्ती बचाओ आन्दोलन

राँची (झारखण्ड): राँची के एचईसी क्षेत्र में बसी बस्तियों को अतिक्रमण के नाम पर एचईसी प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा लगातार उजाड़ने की कोशिश करने, मालिकाना हक की मांग को लेकर लगातार मजबूत हो रहे जनान्दोलन को दबाने के उद्देश्य से आन्दोलनकारियों पर लगाए गए झूठे केस में उन्हें फंसाए रखने व अब तक बस्तीवासियों को नियमित करते हुए मालिकाना हक देने के बिन्दु पर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम ना उठाए जाने के विरोध में 17 फरवरी को रांची में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों छात्र-छात्राओं, महिलाओं एवं हजारों अन्य बस्तीवासियों को लेकर जुलूस निकाला गया। जूलूस राँची के शहीद मैदान से शुरू होकर गोल चक्कर तक गया जहाँ पुलिस-प्रशासन ने जोर जबरदस्ती करते हुए जुलूस को आगे जाने से रोकने की कोशिश की लेकिन जुझारू बस्तीवासी का जुलूस आगे बढ़ता रहा और अंतत: प्रोजेक्ट भवन से कुछ पहले रुककर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की संस्थापिक कॉ. केया डे ने की। उन्होंने कहा कि सरकार एचईसी क्षेत्र में बड़े-बड़े शॉपिंग माल, होटल और रेस्टोरेण्ट खोलने के उद्देश्य से बड़े-बड़े पूंजीपतियों को यह जमीन देने की योजना बना रही है। लेकिन सरकार को उन लाखों लोगों की कोई फिक्र नहीं है जो दिन भर मजदूरी करके, ठेला व रिक्शा चलाकर और सब्जियाँ बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते है।

बस्ती बचाओं संघर्ष समीति के संयोजक विनय कुमार ने भी सभा को सम्बोधित किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि समस्त बस्तीवायिों को नियमित करते हुए मालिकाना हक दिया जाए और समिति के आन्दोलनकारियों पर लगाए गए सभी झूठे केस वापस लिये जाएं।

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय में 48 घंटे का धरना

दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू किए गए चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के खिलाफ ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की दिल्ली राज्य कमेटी के तत्वावधान में 24 से 26 फरवरी तक 48 घंटे का धरना आयोजित किया गया। धरने का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय में कला संकाय के गेट पर किया गया था। धरना स्थल को आजादी आंदोलन व पुनर्जागरण के मनीषियों के उद्धरणों तथा संगठन द्वारा संचालित आंदोलन की तस्वीरों से सजाया गया। धरना स्थल को पुलिस ने बैरिकैड और कार्डन करके रख दिया था और लाइट भी काट दी थी लेकिन अथोरिटी की ओर से उठाये गये ये सब दमनकारी कदम छात्रों की अदम्य भावना को दबा न पाये। धरने के पहले दिन हुई सभा का उद्घाटन अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के दिल्ली राज्य संयोजक प्रो. नरेन्द्र शर्मा ने किया। सभा को दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) की अध्यक्ष प्रो. नन्दिता नारायण, किरोड़ीमल कॉलेज से प्रो. खालिद अशरफ व ए.आई.डी.एस.ओ. के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रशान्त कुमार ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता ए.आई.डी.एस.ओ. के दिल्ली राज्य अध्यक्ष व संगठन के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉमरेड भास्करानन्द ने किया।

सभा के दूसरे दिन हुई सभा में दूसरे छात्र संगठनों को आमंत्रित किया गया था। इस दिन हुई सभा को आइसा के दिल्ली विश्वविद्यालय के इंचार्ज कॉमरेड नीरज कुमार व परिवर्तनकामी छात्र संगठन से कॉमरेड दीपक के साथ ही ए.आई.डी.एस.ओ. के दिल्ली राज्य सदस्य कॉमरेड रवि कुमार, मो. आसिफ व कृष्णेन्दु मुखर्जी ने संबोधित किया।

धरना सभा को सम्बोधित करते हुए नीचे (बाएं से दाएं): प्रो नरेन्द्र शर्मा, कॉमरेड प्रताप सामल और कॉमरेड भास्करानन्द, ऊपर बाएं से सभा को सम्बोधित करती हुई प्रो. नन्दिता नारायण

26 तारीख को करीब 12 बजे विभिन्न कॉलेजों से छात्र धरना स्थल पर एकत्रित हुए और विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में जुलूस निकाला। जुलूस को कला संकाय, रामजस कॉलेज, हिन्दू कॉलेज व किरोड़ीमल कॉलेज में निकालते हुए चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम व कुलपति की तानाशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस के बाद धरना स्थल पर हुई सभा को एआईडीएसओ के पूर्व अध्यक्ष और सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल के साथ ही प्रो. नरेन्द्र शर्मा, एआईडीएसओ के दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड रवि कुमार, सत्यवती कॉलेज (सांध्य) के छात्र मोहित, जाकिर हुसैन कॉलेज से सोनू व दिल्ली विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के छात्र आशुतोष ने संबोधित किया। सभा का संचालन संगठन के प्रदेश सचिव कॉमरेड प्रशान्त कुमार ने किया। इसी बीच संगठन के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड राहुल सरकार और कृष्णेन्दु मुखर्जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने कुलपति के नाम एक ज्ञापन उनके अनुपस्थित होने के कारण विश्वविद्यालय के डिपुटी डीन को सौंपा। जोरदार नारों के साथ आम छात्र व शिक्षक समुदाय को इस आंदोलन को और भी तेज करने की अपील तथा इस आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुंचाने की शपथ के साथ 48 घंटे के धरने का समापन हुआ।

ओबीसी छात्रों की फीस रियायत वापस लेने की सरकारी चाल के खिलाफ प्रतिवाद

बैंगलोर (कर्नाटक) : एआईडीएसओ की जिला कमेटी ने बीसीएम छात्रों को प्रदान की जाने वाली फीस रियायत को वापस लेने के कर्नाटक सरकार के घृणित फैसले के खिलाफ 19 फरवरी को मैसूर बैंक सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया। इस फैसले की वजह से हजारों अल्पसुविधाप्राप्त छात्र फीस रियायत से वंचित हो जाएंगे। इन फासीवादी और गैर जनतांत्रिक गाइडलाइनों की एआईडीएसओ ने निन्दा की और इस नीति के खिलाफ आन्दोलन छेड़ने का आह्वान किया। एआईडीएसओ राज्य कमेटी अध्यक्ष कॉमरेड वी.एन. राजशेखर ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा, ''5 अक्टूबर 2013 के सरकारी आदेश के मुताबिक सरकार ने बीसीएम छात्रों को दी जाने वाली फीस रियायत को वापस लेने का फैसला लिया है और अब से उन्हें पूरी फीस देनी होगी। इस नीति के अनुसार बीसीएम छात्रों द्वारा अदा की गई अतिरिक्त फीस डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) स्कीम के मुताबिक छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस प्रकार अदा की गई अतिरिक्त फीस को वापस पाने के लिए छात्रों को ऑनलाइन एक फार्म भरना होगा। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि यह नीति वर्ष 2013-14 से ही प्रभावकारी होगी जिसका मायने है कि छात्रों को पिछली अवधि की अतिरिक्त फीस भी भरनी पड़ेगी। फीस रियायत को हासिल करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए हैं: 1) छात्र/छात्रा द्वारा किसी आन्दोलनों या हड़तालों में हिस्सा न लिया गया हो। 2) छात्र/छात्रा को सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत अंक हासिल करने चाहिए और उसकी हाजरी कम नहीं होनी चाहिए। 3) छात्र/छात्रा के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

सरकार द्वारा तय की गई ये शर्तें लम्बे अर्से से प्राप्त फीस रियायत के लाभ को ही लाखों गरीब छात्रों से छीन लेंगी। यह एक सामान्य परिघटना है कि 70% से अधिक ग्रामीण छात्र अंग्रेजी भाषा में फेल हो जाते हैं। अब से वे निश्चित ही फीस रियायत को गवां देंगे। विसंगतियों या यूनिवर्सिटियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिवाद करना गैर कानूनी गतिविधि बन जाएगा और यदि छात्र इनमें हिस्सा लेते हैं तो वे इस लाभ को खो देंगे। एआईडीएसओ फासीवादी और गैर-जनतांत्रिक कृत्य के रूप में इस नीति की निन्दा करती है।

एक अल्पसुविधा प्राप्त छात्र को उसी समय फीस रियायत मिलनी चाहिए जब वह फीस अदा करता है बल्कि लम्बे अर्से बाद नहीं जब वह छात्र नहीं रहेगा। हाल के दिनों में फण्डों की कमी का हवाला देते हुए सरकार ने फीस रियायत देने की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर लिया है। लेकिन अब मौजूदा आदेश में उल्लेखित धारा 'मीन्स एण्ड मैरिट' के अनुसार अधिकतम छात्रों को फीस रियायत से वंचित कर देने को कानूनी बना दिया गया है।

एआईडीएसओ के बैंगलोर जिला कमेटी सचिव कॉमरेड रविनन्दन बीबी ने विसंगतियों पर बोला जो राज्य में बीसीएम हॉस्टलों में साफ दिखाई देती हैं। इस अवसर पर अन्य वक्ता बैंगलोर जिला कमेटी की अध्यक्षा कॉमरेड अश्वनी के. एस. ने कहा, ''इस घृणित नीति के खिलाफ छात्रों को राज्य भर में जोरदार आन्दोलन विकसित करने चाहिएं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस फासीवादी आदेश को तुरन्त वापस लिया जाए।''

प्रोग्राम की अध्यक्षता एआईडीएसओ बैंगलोर जिला कमेटी उपाध्यक्ष कॉमरेड अजय कामथ द्वारा की गई।

देश भर में मनाया...

(पृष्ठ 4 का शेष)

के लिए जोरदार सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन छेड़ने की अपील की

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में जनवादी, धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति लागू करने, सभी को रोजगार देने, तब तक न्यूनतम वेतन के आधे जितना बेरोजगारी भत्ता देने, सभी खाली पड़े पदों को स्थायी नियुक्ति कर भरने, सरकारी स्कूल-कॉलेज खोलने, खेलों को पैसे व राजनीति से मुक्त करने, आवेदन शुल्क, प्रवेश परीक्षा, पात्रता परीक्षा समाप्त करने की भी मांग की गई।

प्रदर्शनकारियों को एसयूसीआई(सी) की राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड राजेन्द्र सिंह, ऑल इण्डिया डीवाईओ के कॉ. बलवान सिंह, अनिल, अजय सिंह, देवेन्द्र सिंह, ओमबीर, संदीप, हवासिंह 'संघर्ष', कुलदीप तथा छात्र नेता कॉ. चंचल घोष, हरीश कुमार, उमेश कुमार मौर्य, रूपेश, बिजेन्द्र, विक्रम, कविता, प्रतिभा, आभा, परवीन आदि अनेक शामिल थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्र-युवाओं की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा और आन्दोलन निरन्तर जारी रहेगा।

गुजरात के शहर सूरत में 27 फरवरी को चन्द्रशेखर आजाद दिवस मनाते हुए छात्र-नौजवान

लोकसभा चुनाव..

(पृष्ठ 2 का शेष)

का एक तबका और युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो हमारे विश्लेषण में बुर्जुआ वर्ग की ही एक पार्टी है। सीआईआई के तत्वावधान में हाल में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में 'आप' नेता श्री केजरीवाल द्वारा यह रुख पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। उक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इस बात की घोषणा की कि यह पार्टी पूँजीपतियों के खिलाफ नहीं है और निजीकरण की प्रक्रिया में उनका पक्का यकीन है।

देश की इस अंधकारपूर्ण स्थिति में जब फासीवाद के बादल देश के राजनीतिक क्षितिज पर मंडरा रहे हैं, शोषित जनता के लिए एकमात्र उम्मीद इस युग के महान मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा स्थापित भारत के सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) है। अपने जन्म काल से ही यह पार्टी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतन से लैस होकर केन्द्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों, पूँजीवादी शोषण और साम्राज्यवादी हमलों के खिलाफ देश भर में मजदूर वर्ग के संघर्षों तथा जनवादी जन आंदोलनों को संगठित कर रही है।

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) का यह सुविचारित मत है कि इस शोषणमूलक पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा उपजी तमाम समस्याओं का हल पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति के जरिये ही संभव है। हालांकि, मजदूर वर्ग को वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक और सांस्कृतिक तौर पर तैयार करने के लिए उच्च संस्कृति और नैतिकता के आधार पर वर्ग-संघर्षों और जनवादी जन आंदोलनों को निर्मित करना अत्यंत आवश्यक है। जनवादी और धर्मनिरपेक्ष जन आंदोलनों को विकसित करने पर पूरा ध्यान देते हुए पार्टी युवा पीढ़ी को शिक्षित तथा प्रेरित करने के लिए भारतीय नवजागरण के महान अग्रदूतों तथा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों की जयन्तियाँ और मृत्यु वार्षिकियाँ मनाती आ रही है।

जब तक मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम क्रांति के लिए तैयार नहीं हो जाता और जब तक वह संसदीय मोह में फंसा हुआ है, तब तक सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)संसदीय मोह दूर करने के लिए साथ-साथ इन बुर्जुआ और छद्म कम्युनिस्ट पार्टियों का राजनैतिक तौर पर पर्दाफाश करने और इस प्रक्रिया में जनता में राजनैतिक चेतना पैदा करने के उद्देश्य से चुनावों में भाग लेना जरूरी समझती है और चुनावों में प्रतिद्वन्द्विता करने का दूसरा कारण यह है कि विजयी होने पर संसदीय फोरम में जनता के विरोध की आवाज को उठाना और संसद के बाहर के गैर संसदीय आंदोलनों को संगठित करना, मजबूत करना और परिपूरक बनाना।

इसलिए इस संसदीय चुनाव में यद्यपि विभिन्न झंडों वाली अनेक पार्टियाँ प्रतिद्वन्द्विता कर रही हैं, लेकिन वास्तव में दो ही ताकतें हैं, दो ही तरह की राजनीति हैं। एक तरफ शोषक बुर्जुआ वर्ग की प्रतिनिधि कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय पार्टियां हैं तथा उन्हीं की राह पर चलने वाली सोशल डेमोक्रेटिक सीपीआई, सीपीएम हैं। दूसरी तरफ शोषित वर्ग और समस्याओं में ग्रस्त विशाल जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) है। बाकी पार्टियों की राजनीति पूँजीपति वर्ग और व्यवस्था की सेवा करना और देश को और बर्बादी की ओर ले जाना है, जबकि सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) की राजनीति वर्ग संघर्षों व जन संघर्षों को संगठित करना और अंततः गांवों से लेकर शहरों तक, खेत-खलिहानों से लेकर फैक्ट्री-कारखानों तक जनता को उसकी कमेटियों में संगठित कर उसकी राजनैतिक शक्ति को जन्म देने पर लक्षित है ताकि एक दिन जनता अपने भाग्य का फैसला खुद कर सके।

जन जीवन के भविष्य के लिए काफी अहम आगामी लोकसभा चुनाव में जनता को तय करना है कि वह पूंजीवादी शोषण को चलते रहने देगी या फिर उससे मुक्ति के लिए संघर्ष को ताकतवर बनायेगी।

अभिवादन सहित

प्रभास घोष
महासचिव,
एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)

आगामी लोकसभा चुनाव, 2014 में सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) 82 सीटों पर चुनाव लड़ेगी

क्र. संख्या	राज्य चुनाव व सीटों की संख्या	
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	असम	6
3.	बिहार	4
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	दिल्ली	1
6.	गुजरात	1
7.	हरियाणा	2
8.	झारखण्ड	2
9.	कर्नाटक	6
10.	केरल	6
11.	मध्य प्रदेश	2
12.	उड़ीसा	5
13.	उत्तर प्रदेश	3
14.	तमिलनाडू	3
15.	त्रिपुरा	1
16.	पश्चिम बंग	37
16 राज्यों में कुल संसदीय सीट		**82**

युक्रेन में गृहयुद्ध ..

(पृष्ठ 1 का शेष)

परस्त मीडिया ने संघर्ष का चित्रण जनवादी जनप्रिय आन्दोलन और एक निरंकुश तानाशाह के बीच संघर्ष के रूप में किया था। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व दक्षिणपंथी, उग्रराष्ट्रवादी, नस्लवादी और नवफासीवादी ग्रुपों जैसे स्वोबाडा, राइट सैक्टर, फादरलैण्ड पार्टी, यूडीएआर पार्टी इत्यादि के तहत ताइमोसेंको, यात्स्नेपुक, क्लिश्को और ताहिनिबोक जैसे नेताओं द्वारा किया जा रहा था। राष्ट्रपति यांनुकोविच के खून के प्यासे थे यूएसए और ईयू। वे हल्ला मचा रहे थे कि उन्हें लोगों की इच्छा के सामने झुकना चाहिए और सत्ता सौंप देनी चाहिए। यूएस अण्डर सैक्रेट्री ऑफ स्टेट विक्टोरिया नुलांद और कीव में अमेरिकी राजदूत के बीच हुई टेलिफोन वार्ता लीक हो गई जिसने साम्राज्यवादी षड्यन्त्र को स्पष्ट तौर पर सामने ला दिया कि वे चुने हुए राष्ट्रपति को सत्ताच्युत करके ताबेदार कठपुतली बिठाना चाहते हैं और जो विरोधी राजनीतिकों की साम्राज्यवादी तिकड़मबाजियों के बारे में खुली स्वीकारोक्ति है; साथ ही साथ यह पूँजीवादी हिस्सेदारों-अमेरिका और ईयू के बीच बर्बर प्रतियोतिगता को भी दर्ज करती है। जैसे ही सशस्त्र संघर्ष, आगजनी और तबाही तीव्रतर हुई अंततः पश्चिमी शक्तियाँ विरोधियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए यांनुकोविच को मजबूर करने में सफल हुई जिसमें कहा गया कि 2004 के संविधान पर लौटा जाएगा जो राष्ट्रपति को कम शक्तियाँ प्रदान करता है, एक नई गठबंधन सरकार बनाई जाएगी और दिसम्बर 2014 से पहले नए चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन साम्राज्यवादी षड्यन्त्रकारियों के लिए यह काफी नहीं था और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के एक तबके को समझौता खारिज करने के लिए भड़का दिया। अगले दिन प्रदर्शनकारियों ने प्रेसिडेन्शियल प्रशासनिक भवनों पर कब्जा कर लिया और संसद ने यांनुकोविच को सत्ता से हटाने के लिए मत दिया और 25 मई को नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। पश्चिम परस्त विपक्षी नेता युलिया ताईमोशेंको को जेल से रिहा कर दिया गया और उसे अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। यूएस/ईयू आक्रमण का उद्देश्य डैमोक्रेसी लाना नहीं था बल्कि यूक्रेन में लूटेरी पूँजी के प्रवेश और इसकी श्रम शक्ति तथा प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को सुगम बनाना था। यूक्रेन में साम्राज्यवादियों की जीत के मजदूर वर्ग और दुनिया भर के उत्पीड़ित लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। यूक्रेन में साम्राज्यवादी षड्यन्त्र की इण्टरनेशनल एण्टी इम्पीरियलिस्ट को-आर्डिनेटिंग कमेटी (आईएसीसी) घोर निन्दा करती है और पक्का यकीन रखती है कि साम्राज्यवादी षड्यन्त्रों को केवल दुनिया भर के लोगों के दृढ़निश्चयी और संयोजित एक्शन के द्वारा ही नाकाम किया जा सकता है। आईएसीसी मजदूर वर्ग और दुनिया के उत्पीड़ित लोगों का जोरदार तरीके से नारा बुलन्द करने का आह्वान करती है, 'साम्राज्यवादियों यूक्रेन से दूर हटो!'

झारखण्ड में कॉमसोमोल का कैम्प

रांची : 23 फरवरी को यहां सैक्टर-2 में कॉमसोमोल का एक दिवसीय कैम्प आयोजित किया गया। इसमें रांची जिला के विभिन्न इलाकों से चयनित 55 कामसोमोल सदस्यों ने भाग लिया। कैम्प के दौरान '' कॉमसोमोल क्या है?'' विषय पर चर्चा हुई। एसयूसीआई (सी) के झारखण्ड राज्य सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति ने किशोर-किशोरियों को सम्बोधित किया। इसके अलावा कैम्प में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये। इस दौरान कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किये गये और क्रान्तिकारी फिल्म भी दिखाई गई। केम्प का संचालन वह्निशिखा समाजपति, अभिषेक सिन्हा और संजीत चक्रवर्ती ने किया।

अन्य विवरण फॉर्म 4 (नियम 8 देखिए)

प्रकाशन का स्थान	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशन की अवधि	: पाक्षिक
मुद्रक का नाम	: सत्यवान
राष्टीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सम्पादक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
उन व्यक्तियों के नाम एवं पते जो अखबार के स्वामी है या जो कुल पूँजी के एक प्रतिशत या उससे अधिक के हिस्सेदार हैं	

मैं सत्यवान, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि दिए गए उपरोक्त विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य है।

दिनांक : 5 मार्च, 2014

ह. सत्यवान
प्रकाशक के हस्ताक्षर

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing : 5 March, 2014

अमेरिका द्वारा उत्तरी कोरिया के खिलाफ मानवाधिकार हनन की अफवाह फैलाने के घृणित प्रयास की

एसयूसीआई (सी) ने की घोर निन्दा

23 फरवरी, 2014 को एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित बयान जारी किया:

सदा की तरह संयुक्त राष्ट्र को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करते हुए साफ तौर से आरोपित मानव अधिकार रिपोर्ट पर आधारित मानवाधिकार हनन के गढ़े हुए आरोप लगाकर अति घृणित अंतर्राष्ट्रीय लुटेरे और मानवजाति के नम्बर एक दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा समाजवादी उत्तरी कोरिया को कटघरे में खड़ा करने के अति घृणित और दुष्टतापूर्ण प्रयास की हम घोर निन्दा करते हैं। लगातार युद्ध धमकी, सामरिक घेराबन्दी, दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिबंध और धूर्ततापूर्ण राजनयिक तिकड़मबाजियों सहित हर संभव प्रयास के बाद भी उत्तरी कोरिया को झुकाने में नाकाम पेण्टागन के युद्ध सरगनाओं ने अब कीचड़ उछालने का रास्ता अपनाया है। उसके मौलिक मानवाधिकारों के अति निर्लज्ज व जघन्य ट्रैक रिकार्ड को हर कोई जानता है। जैसा कि इनके द्वारा वियतनाम युद्ध के दौरान बेरहम हत्याओं और जनसंहारक हथियारों के इस्तेमाल में, सार्वभौम इराक पर जबरदस्ती कब्जा करने में जहाँ शिशुओं के कुचले चेहरों, बेगुनाह नागरिकों के चारों ओर बिखरे कटे हुए अंगों और धड़ों ने रोमन साम्राज्य की पाश्विक बर्बरता की याद दिला दी थी, अफगानिस्तान में दीर्घस्थाई हिंसा में, लीबिया में मिलिट्री हस्तक्षेप के जरिए सत्ता परिवर्तन कराने, सूडान में गृहयुद्ध का षड्यन्त्र रचने, सोमालिया, हैती और अन्य अफ्रीकी देशों में उत्तेजना भड़काने वाले एजेण्टों को रोपित करके, विध्वंसक और तोड़फोड की कार्रवाइयों को भड़काने, यहाँ तक कि सरकार के पदस्थ मुखियाओं का अपहरण करने में और सामरिक शक्ति की शान दिखाते हुए दुनिया भर में निर्लज्ज दादागिरी बेशर्मी के साथ थोपने से साफ प्रमाणित हो चुका है। अबु गरीब और गुआंतानामो बे की जेलों में कैदियों को दी गई बर्बर यातनाओं और क्रूर, अमानवीय तथा शर्मनाक बर्ताव का जो विवरण बंदी प्रत्यक्षीकरण वकीलों के गैर-वर्गीकृत नोट्स से सीधा प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ अन्य अमेरिकी जेलों के कैदियों के साथ तमाम अन्तर्राष्ट्रीय ट्रीटियों, कन्वेंशनों और घोषणाओं का उल्लंघन करते हुए किया जाने वाला दुर्व्यवहार इस बात की साफ गवाही देता है कि कैसे पूरी तत्परता के साथ अमेरिकी सरकार द्वारा मानव अधिकार पैरों तले कुचले जा रहे हैं। अमेरिकी फार्मों पर सैकड़ों हजार बच्चे प्रतिदिन 10 या 10 से अधिक घण्टों तक काम करते हैं और वे कीटनाशक विषाक्तता, गर्मी जनित बीमारियों, चोटों, जीवन भर की अपंगता और मृत्यु के खतरे में हैं। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए, मजबूती से समाजवाद की रक्षा कर रहे उत्तर कोरिया के खिलाफ कथित 80 भगोड़ों की गवाही और तथाकथित उपग्रह चित्रों को आधार बनाकर ये हत्यारे झूठा प्रचार चलाने की जिम्मेदारी खुद पर आयद करने की अनधिकार चेष्टा का साहस कर रहे हैं। यह भी गौरतलब है कि गढ़े गए और निराधार आरोपों के जरिए उत्तरी कोरिया को नियमित अंतरालों पर प्रताड़ित करना, वहाँ समाजवाद का तख्ता पलटने के लिए अमेरिकी शासकों द्वारा उठाए जा रहे षड्यन्त्रकारी कदमों का हिस्सा बन चुका है।

हम दुनिया के साम्राज्यवाद-विरोधी शान्तिकामी लोगों का आह्वान करते हैं कि वे अमेरिकी साम्राज्यवादियों और उनके चाटुकारों के निहित उद्देश्य से प्रेरित इस प्रचार से भ्रमित न हों और समाजवादी उत्तरी कोरिया के साथ मजबूती से खड़े हों।

तुच्छ चुनावी फायदों के लिए ही आंध्र प्रदेश का विभाजन

एसयूसीआई(सी) ने किया जोरदार विरोध

19 फरवरी 2014, को एसयूसीआई (सी) महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित बयान जारी किया:

डैमोक्रेसी की निर्लज्ज अवहेलना और किसी नीतिगत प्रस्ताव को पेश करने और पास कराने के तमाम संहिताबद्ध तौर-तरीकों, प्रक्रियाओं और अभ्यासों को पैरों तले रौंदते हुए, यहाँ तक कि संसदीय कार्यवाही के सीधे प्रसारण को जानबूझ कर बन्द करते हुए जिस प्रकार वस्तुत: पिछले दरवाजे से अति विवादास्पद अलग तेलंगाना बिल को मुख्य विपक्षी दल भाजपा के साथ सांठगांठ करके कांग्रेस-नीत शासक यूपीए-2 द्वारा पास कराया गया उसकी भर्त्सना करने लायक शब्द नहीं हैं। इस बहाने की आड़ में आंध्र राज्य को विभाजित करने का कदम उठाया गया है कि छोटे राज्यों में विकास तेजी से होता है। यह तेलगू भाषी लोगों के बीच दरार डालने और शासक पूँजीपति वर्ग तथ इसके राजनीतिक एजेण्टों की संकीर्ण स्वार्थ सिद्धि पर लक्षित है ताकि चुनावी फायदों की फसल काटने के मद्देनजर मेहनतकश लोगों को बांट कर रखा जा सके और उत्पीड़ित लोगों की कीमत पर धन और सत्ता सुख भोगने के लिए मंत्री बना जा सके और तमाम बुराइयों को पनपा रहे दमनकारी पूँजीवादी शोषण के खिलफ संयुक्त प्रतिवाद आन्दोलन के उभार को रोका जा सके। निहित स्वार्थी हलकों द्वारा अभिप्रेरित प्रचार कि रायलसीमा और तटीय आंध्र के मुकाबले तेलंगाना पिछड़ा हुआ है तथ्यात्मक रूप से गलत है, जिसकी संपुष्टि श्री कृष्ण कमीशन द्वारा भी की गई है कि तेलंगाना इलाके के क्षेत्रों की तरह ही रायलसीमा और तटीय आंध्र के अनेक क्षेत्र घोर पिछड़ेपन का शिकार हैं क्योंकि असमान विकास पूँजीवाद का लाक्षणिक चरित्र है और पूँजीवाद के मौजूदा मरणासन्न दौर में यह और भी स्पष्ट और तीव्रतर हो गया है। कांग्रेस, भाजपा, टीडीपी, टीआरएस और सीपीआई जैसी पार्टियाँ जो आंध्र प्रदेश के बंटवारे का खुल्लमखुल्ला समर्थन कर रही हैं साथ ही साथ कांग्रेस के विभिन्न धड़े, टीडीपी और ऐसे ही अन्य जो इसका विरोध कर रहे हैं सभी इस मुद्दे पर घपलेबाजी कर रहे हैं, भावनाएं भड़का रहे हैं और आगामी संसद तथा विधान सभा चुनावों पर नजरें गड़ाए हुए ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें जनहित से और जनजीवन की ज्वलन्त समस्याओं के समाधान से कोई सरोकार नहीं है। मेघालय, मणीपुर और त्रिपुरा जैसे छोटे पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ या झारखण्ड जैसे नवगठित राज्यों तक विभिन्न छोटे राज्यों के गठन से उत्पीड़ित लोगों को कोई राहत नहीं मिली है बल्कि उनकी दुर्दशा और कंगाली में इजाफा ही हुआ। इसके विपरीत इन राज्यों के लोगों ने क्षोभ के साथ नोट किया है कि उनके अन्दर से ही एक 'मलाईदार तबका' उभर कर आ गया है जो तमाम पावर, पोजीशन, सुविधाओं का सुख भोग रहा है और तेजी से धन बटोर रहा है तथा शासक वर्ग का दुमछल्ला बन गया है। इसके अलावा, तेलंगाना का गठन अलगाववाद को हवा देगा और विदर्भ, बोडोलैण्ड, गोरखालैण्ड आदि के लिए मांगों को उभार देगा। अपने घृणित चुनावी एजेण्डे को पुख्ता करने के प्रयास में वोट के सौदागरों ने देश को ऐसे एक गंभीर खतरे के कगार पर ला खड़ा किया है जिसमें अलगाववादी-क्षेत्रीयतावादी आन्दोलनों और मौजूदा राज्यों के निरन्तर विभाजन का नया दौर शुरू हो जाएगा।

इसलिए, हम देश के लोगों से, विशेषकर आंध्र प्रदेश के उत्पीड़ित लोगों से आह्वान करते हैं कि वे राज्य को बांटने के पीछे शासक पूँजीपति वर्ग और इसके सेवादारों के घृणित उद्देश्य को समझें और ऐसे कदमों, जिनका उद्देश्य उन्हें बांटना और सत्य उजागर करने की ताकत से उन्हें महरूम करना है, उनका जोरदार प्रतिवाद करने और रोकने के लिए आगे आएं और अपनी पांतों को मजबूत करें। देशव्यापी संयुक्त सशक्त सतत जनवादी आन्दोलन ही ऐसे घृणित बुर्जुआ षड्यन्त्र को रोक सकता है।

बिजली दर में प्रस्तावित बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ धरना

पटना (बिहार) : महंगी बिजली-विरोधी संघर्ष मंच के घटक दलों / संगठनों द्वारा 24 फरवरी को महंगी बिजली-विरोधी संघर्ष मंच द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर धरना दिया गया। नेताओं ने कहा कि कुटीर ज्योति (बीपीएल) का वर्तमान दर 55 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिसमें पूर्व की दर से लगभग 4 गुनी वृद्धि की गयी है। 2 किलोवाट के लोड पर घरेलू (ग्रामीण) मीटर रहित कनेक्शन के लिए वर्तमान में जो दर 160 रुपये प्रति माह है, उसको बढ़ाकर 350 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। यह दोगुना से भी ज्यादा है।

अपने संबोधन में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. अरूण कुमार सिंह ने कहा कि सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य की तरह बिजली को आज साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के वर्तमान दौर में एक व्यावसायिक धंधा और मुनाफा कमाने का जरिया मान लिया है। केन्द्र सरकारों की राह पर चलते हुए नीतीश कुमार सरकार ने बिहार विद्युत बोर्ड का विखंडन कर इसे पांच कम्पनियों में बांट दिया है। फिडरों से वितरित होने वाली बिजली की फ्रेंचाइजी निजी कम्पनियों / व्यक्तियों को दिये जाने की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि गलत विपत्र भेजकर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है, जबकि बड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत से बड़े-बड़े औद्योगिक व व्यवसायिक घरानों द्वारा की जा रही बिजली चोरी पर रोक नहीं लगायी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और उनके पास लाखों के बकाये की सख्ती से वसूली नहीं होती। कॉ. सिंह ने सरकार और बिजली कम्पनियों के इस दोहरे चरित्र की कड़ी निन्दा की।

धरने को सीपीआई के चक्रधर प्रसाद सिंह, सीपीआई (एम) के सारंधर पासवान, एमसीपीआई (यू) के राजा बाबू, सीपीआई (एम-एल) के अरविन्द सिन्हा, जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के च. अ. प्रियदर्शी, सर्वहारा जन मोर्चा के अजय कुमार सिन्हा, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के वकील ठाकुर, जनवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के नृपेन्द्र कृष्ण महतो, अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी) के बाल गोविन्द सिंह, समाजवादी जन परिषद के संजय श्रीवास्तव, बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन (ऑटो यूनियन) के धीरेन्द्र भारती तथा असंगठित क्षेत्र कामगार यूनियन (बिहार) के राम नन्दन प्रसाद ने संबोधित किया।

इसके अलावा धरने को सीसीआई के सतीश, श्रम मुक्ति संगठन के जय प्रकाश, लोकतांत्रिक रक्षा अभियान के अक्षय कुमार, प्रगतिशील जन पहल के प्रो. देवेन्द्र प्रसाद, लोक परिषद के रूपेश, शिक्षाविद प्रो. विनय कुमार कंठ, प्रो. एम. एन. कर्ण, अर्थशास्त्री प्रो. नवल किशोर चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता नागेश्वर प्रसाद, अरशद अजमल, राजनीतिक कर्मी सत्य नारायण मदन, विजय बहादुर सिंह आदि ने भी संबोधित किया।

धरने का संचालन सात सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने किया, जिसमें एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉ. शिव शंकर भी थे।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. सत्यवान द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित। दूरभाष : 011-25726631, Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com